Import of steels

3357. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHAND ARE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether as reported in the Indian Express dated the 27th December, 1991, 35,000 tonnes of unwanted steel billets were imported at a cost of over Rs. 18 crores in foreign exchange by the MMTC;

(b) if so, in what circumstances the import was made;

(c) whether the entire equity of billets containing various impurities like copper, was unsuitable for rolling; and

(d) how these billets have been utilised?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Against an indent of SAIL, MMTC finalised contract with M/s. Daval, France for import of 35,000 tonnes of steel billets valued at Rs. 18.27 crores, including customs duty etc. The outgo of foreign exchange involved was Rs. 9.74 crores. The purpose of the import was to use it for making light structurals at the Bhilai Steel Plant.

(c) and (d) Part of the quantity supplied by M/s. Daval, France had copper contents higher than permitted under the contract specifications. Of the total quantity of 35,000 tonnes of billets imported, about 10,000 tonnes were used by Railways and the balance, approx. 25,000 tonnes were used by SAIL in their Durgapur Steel Plant instead of Bhilai Steel Plant.

Failure of Tea Boards to Benefit the small tea growers of Assam

3358. SHRI DAVID LEDGER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the regional office of the Indian Tea Board at Guwahati has failed to benefit the small tea growers of Assam;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government propose to provide more administrative and financial powers to the regional office; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Necessary administrative and financial powers have already been delegated to the zonal office of the Board. Chief Regional Executive is empowered to receive, process and distribute loans and subsidy in respect of tea gardens under his jurisdiction.

The delegated powers include:

(i) Tea Plantation Finance Scheme : upto 50 hectares.

(ii) Tea Machinery and Irrigation equipment Hire Purchase Scheme. : upto Rs. 7.5 lakhs against the maximum ceiling of Rs. 10 akhs.

(iii) Replantation and Rejuvenation Subsidv Scheme upto 50 hectares. and*

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) के निर्णयों का प्रभाव

3359. श्री महेन्द्र सिंह लाठर:
श्री घूलेश्वर मीणा:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की आठवीं बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस बैठक में लिए गए निर्णयों का विकासशील देशों के साथ-साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) इन निर्णयों के फलस्वरूप भारत को होने वाले लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उरूग्वे दौर की अगली वार्ता के लिए क्या आधार तैयार किए गए हैं?

वाणिजय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड 8) का 8 वां सत्र कार्टगेना

डि इण्डियास, कोलम्बिया में दिनांक 8 से 25 फरवरी, 1992 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य राज्य मंत्री ने किया था।

इस सम्मेलन में विकास के लिए नई भागीदारी की मांग करते हुए एक राजनीतिक घोषणा पारित की गई। सम्मेलन में कार्यसूची मदों के संबंध में नीतियां निर्धारित करते हुए, "स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय कार्यवाही को सुदृढ़ करने" पर एक दस्तावेज भी अंगीकार किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में इस सम्मेलन ने यह मांग की कि सभी के, खासकर विकासशील देशों के लाभ के लिए विश्व व्यापार को और अधिक उदार बनाने और इसके विस्तार के लिए संरक्षणवाद को समाप्त करने तथा उसे उलटने की कार्रवाई की जाए और निरंतर विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण और व्यापार नीतियां परस्पर समर्थनकारी हो। इसमें यह भी मांग की गई कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरूग्वे दौर के त्वरित, संतुलित, व्यापक और सफल परिणाम के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति को सुदृढ़ किया जाए। प्रौद्योगिकी के बारे में सम्मेलन ने यह बात स्वीकार की कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता एक मूल कारक है, इसलिए यह सिफारिश की गई कि ऐसी नीतियों और उपायों पर जोर दिया जाए जिससे विकासशील देशों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हो सके। विकास प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए, सम्मेलन ने विकसित देशों से मांग की कि वे विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग को सुलभ बनाने के उपायों पर विचार करें। ऋण के मुद्दे पर, सम्मेलन ने कम आय, परन्तु अधिक ऋण बोझ वाले उन देशों के कार्यों की प्रशंसा की जो काफी बड़ी कीमत पर ऋण को चुकाना तथा अपनी ऋणयोग्यता की रक्षा करना जारी रखे हुए हैं। सम्मेलन ने मांग की कि ऐसे देशों को संसाधन आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सम्मेलन ने विचार व्यक्त किया कि विकासशील देशों में संरचनात्मक सामंजस्य की, प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सहायता देने एवं उसके वित्त पोषण की आवश्यकता है। सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों के लिए सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त रूप से अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उसने विकसित देशों का आह्वान किया कि उन्होंने अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत ओ०डी०ए० को देने के संबंध में जिस अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने का समझौता किया था उसे कार्यान्वित किया जाए। सेवाओं के मुद्दे पर, सम्मेलन में यह सहमति हुई कि विकासशील देशों के निर्यात हित की आपूर्ति के तरीकों और क्षेत्रों में बाजार प्रवेश के उत्तरोत्तर बहुपक्षीय उदारीकरण का समर्थन करने के लिए सभी सरकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें सेवाओं की आपूर्ति के लिए श्रम का अस्थायी आदान-प्रदान भी शामिल है। वस्तुओं के क्षेत्र में सम्मेलन में अंकटाड के महासचिव से अनुरोध किया कि वस्तुओं के प्रश्न पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाओं पर बातचीत की जाए जिससे एक संगत अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु नीति बनाने के उद्देश्य से उत्पादकों, विपणन, उद्यमों और अन्य बाजार कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलाकर विचार-विमर्श कर सकेंगे और उक्त नीति में चुनिंदा वस्तु क्षेत्र की खास समस्याओं को ध्यान में रखा जा सकेगा।

सम्मेलन ने स्वीकार किया कि सभी विकास स्तरों पर व्यापक आधार वाले विकास और ठोस आर्थिक निष्पादन कायम रखने के लिए अच्छा प्रबंध एक आवश्यक तत्व हैं।

इस सम्मेलन में लिए गए नीतिगत निर्णय सिफारिशी प्रवृत्ति के हैं और उनका अनुपालन इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समितियों द्वारा किया जाएगा। हमारे और अन्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण से परिणाम सकारात्मक ही हैं।

सम्मेलन में पुन्ता डेल एस्टे घोषणा पत्र के सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को दोहराते हुए सभी भागीदारों, विशेष रूप से प्रमुख व्यापार साझीदारों से यह आग्रह किया गया कि वे विकासशील देशों के खास-खास हितों को ध्यान में रखते हुए उरूग्वे दौर के तात्कालिक, सन्तुलित, विस्तृत तथा सफल निष्कर्ष निकलने के लिए ठोस उपाय करें।

कतिपय चाय बागानों द्वारा करों की चोरी

3360. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चौबुआ टी एस्टेट, डिब्रूगढ़, गंगावरी टी एस्टेट, घोला तिनसुकिया, दुर्गापुर टी एस्टेट, बरबोरुआ, शिवपुरिया टी एस्टेट, पानितुला टी एस्टेट, तिनसुकिया, लिटटू टी एस्टेट, तिनसुकिया अपने उत्पादन को कम करके दिखाते हैं और उत्पाद शुल्क तथा आयकर का कम भुगतान करते हैं;